(b) Central Government does not exercise any statutory control on the price of newsprint. It has been the practice in the past for the Government to indicate the maximum ex-factory price which may be charged by indigenous newsprint producers from time to time on the basis of recommendations of the Bureau of Industrial Costs & Prices. However, the indigenous newsprint mills on their own decided to revise the ex-factory price of newsprint during May/June, 1989.

(c) No, Sir.

Creation of separate pool for Allotment of Government Accommodation for Staff Employed in Delhi

473. PROF. C. LAKSHMANNA : Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that any separate pool for allotment of Government accommodation has been created for the staff employed in various Government Offices located in Delhi in the year 1987-88 and 1988-89;

(b) if so, the names of those offices; and

(c) the number of type IV and above categories of accommodation placed at the disposal of those offices together with the persons entitled to Government accommodation of the respective categories in those offices?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) Rajya Sabha Secretariat Pool has been created in May, 1988.

(c) 29 quarters in type IV
2 quarters in type V A
1 quarter in type VI
1 quarter in type VII

The information regarding the Persons in the Rajya Sabha Sectt. entitled for allotment of Govt. accommodation in these categories is not available with Dte. of Estates.

मुख्तारनामे के आधार पर दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों की बिक्री

474. **श्री शरद यादव** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि डी०डी०ए० के फ्लैट मुख्तारनामे (पावर आफ अटर्नी) के आधार पर ब्लैक में बेचे जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न श्रेणियों के कितने फ्लैट जारी किये गये और इनमें से कितने फ्लैट "पावर आफ अटर्नी" के आधार पर बेचे गए हैं ; और

(ग) इस प्रकार की 'काला बाजारी' को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) यह तथ्य कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों के संबंध में कुछ मामलों में मुख्तारनामे के आधार पर सौदे होते हैं, जो सरकार के ध्यान में हैं ।

(ख) विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अब तक आवंटित किये गये फ्लैटों की कुल संख्या 1,66,471 है । पिछले तीन वर्षों के दौरान अथवा कोई अन्य अवधि में मुख्तारनामे के जरिये हुये सौदों की संख्या की सरकार को जानकारी नहीं है, चूंकि वे किसी सरकारी प्राधिकरण को सूचित नहीं किये जाते हैं ; और

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपेक्षानुसार सुधारों का सिलसिला

प्रारंभ किया है, जिसका उद्देश्य दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों की बिक्री के संबंध में विभिन्न प्रतिबंधों को शिथिल करना अनार्जित वृद्धि के आकलन तथा इसके भुगतान से संबंधित पद्धतियों का सरलीकरण, बिक्री की अनुमति प्रदान करने हेतु पद्धति का सुव्यवस्थीकरण करना है। इन सुधारों का मूलभूत उद्देश्य दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों की खुली बिक्री को सुविधा जनक बनाना और एक उपयुक्त विक्रय विलेख के विकल्प के रूप में मुख्तारनामा के इस्तेमाल में कमी करना है ।

भूमि की चकबन्दी में हुई प्रगति

475. **श्री शरद यादव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भूमि की चकबन्दी के लिये राज्यवार वार्षिक निर्धारित लक्ष्य क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि लोगों ने भूमि की चकबन्दी के विरुद्ध शिकायतें की हैं और मुकदमे दायर किये हैं ;

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार की शिकायतों और मुकदमों की संख्या कितनी है ; और

(घ) चकबन्दी के काम में लगे हुये व्यक्तियों के व्यवहार में सुधार लाने और व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ।

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भूमि जोतों की चकबन्दी के कार्यक्रम के लिये राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं ।

(ख) से (घ) भूमि राज्य का विषय होने के कारण भूमि चकबन्दी कार्यक्रम के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्यों की है। यदि कार्यक्रम के संबंध में शिकायत यदि कोई हो, तो उनकी जांच संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की जाती है । भारत सरकार द्वारा प्राप्त शिकायतों को भी राज्य सरकारों को उचित कार्रवाई के लिये अग्रेषित किया जाता है ।

Setting up of Newsprint Corporation

476. SHRI CHITTA BASU: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether the price of newsprint has of late gone abnormally high;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) whether Government propose to set up a newsprint Corporation for handling allocations, import, stocking and distribution of foreign and indigenous newsprint?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (PROF. K.K. TEWARY): (a) The price of indigenous newsprint has gone up from 28% to 40% compared to the prices prevailing in January, 1988 for 52 gsm newsprint. In the case of imported newsprint there has been increase from 1.9% to 8.3% compared to the previous quarter.

(b) The increase in the prices of newsprint is attributable to the increasing costs of indigenous production and increasing cost of imports.

(c) No, Sir.

Setting up of TV relay centre at Kota

477. SHRI BHUVNESH CHATURVEDI: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to upgrade T.V. relay centre at Kota in Rajasthan; and